Indian Council of World Affairs
Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi

पंद्रहवां सप्रु हाउस व्याख्यान

द्वारा

महामहिम श्री फुमियो किशिडा
जापानी विदेश मंत्री

विषय

"हिंद-प्रशांत के युग के लिए विशेष साझेदारी"

स्थान
सप्रु हाउस, नई दिल्ली
17 जनवरी 2015

राजदूत राजीव कुमार भाटिया, विश्व मामलों की भारतीय परिषद् के महानिदेशक , राजदूतशशांक, पूर्व विदेश सचिव, अतिविशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों,

(आरंभिक भाषण)

राजदूत भाटिया और राजदूत शशांक आपका आरंभिक टिप्पणी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आज विश्व मामलों की भारतीय परिषद् में बोलने का अवसर प्राप्त होने पर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं।

मैं विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ जापान-भारत विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता में भाग लेने के लिए पिछले वर्ष के अंत में भारत का दौरा करने वाला था। तथापि , जापान में आम चुनाव होने के कारण जहां मुझे भी अपनी सीट के लिए चुनाव लड़ना था , दुर्भाग्यवश मैं उस अवसर पर यहां का दौरा नहीं कर सका। जैसा कि मैं मानता हूं कि भारत , जो कि न केवल एशिया का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, में हर कोई जानता है कि चुनाव लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण है और मुझे आशा है कि आप इस स्थिति को समझ सकते हैं।

दो सप्ताह के चुनावी अभियान के दौरान मैं हिरोशिमा के अपने संसदीय क्षेत्र में भी नहीं जा पाया। बल्कि समर्थन मांगने के लिए मैंने पूरे जापान की यात्रा कर ली और मेरे कई सहयोगी यथा संभव चयनित हुए। इसके परिणामस्वरूप, सत्ताधारी दलों को मजबूत विश्वास हासिल हुआ और प्रधानमंत्री शिंजो आबे के तीसरे मंत्रिमंडल की शुरूआत हुई। और मुझे विदेश मंत्री के रूप में पुन: नियुक्त किया गया। अब मेरी पुनर्नियुक्ति के बाद मैं यहां भारत में हूं और इस दौरे को महसूस कर मुझे बहुत खुशी हो रही है जो मैंने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जापान यात्रा के दौरा उनसे वादा किया था।

(हिंद-प्रशांत का युग) देवियों और

सज्जनों,

मैं एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ भारत आया हूं। मैंने अपनी पुनर्नियुक्ति के बाद यात्रा के लिए प्रथम देश के रूप में भारत को चुना क्योंकि मेरा विश्वास है कि भारत और जापान के बीच की साझेदारी विशेष है। यह एक ऐसी साझेदारी है जिसे नए युग को आगे ले जाना चाहिए; एक युग जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक समृद्धि का केन्द्र बन गया है। प्रशांत और हिंद महासागर स्वतंत्रता और समृद्धि के महासागर के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। इस क्षेत्र के आस पास के देशों ने उल्लेखनीय आर्थिक विकास हासिल किया है। हलांकि साथ ही साथ यह भी सही है कि यह क्षेत्र अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से सुभेद्य है। आज, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति और समृद्धि न केवल जापान व भारत के लिए बल्कि संसार भर के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसी मान्यता पर अब मैं अपने विचार को लागू करना चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि इसी विचार पर जापान और भारत के बीच विशेष साझेदारी इस हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भूमिका अदा करनी चाहिए।

महामहिम श्री फुमिया किशिडा, जापानी विदेश मंत्रीपंद्रहवां सप्रु हाउस व्याख्यान देते हुए।

(जापान और भारत द्वारा अपनाए गए मार्ग का सिंहावलोकन)

देवियों और सज्जनों,

भविष्य पर चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं जापान और भारत द्वारा अपनाए गए मार्ग का सिंहावलोकन

करना चाहूंगा।

जैसा कि प्रधानमंत्री अबे ने अपने नए वर्ष के प्रेस सम्मेलन में कहा , जापान इस युद्ध के संबंध में गंभीर पश्चाताप के आधार पर एक लोकतांत्रिक राज्य का निर्माण किया है जिसने इस युद्ध की समाप्ति के बाद 70 वर्षों से अधिक समय से मानवाधिकार और कानून के राज्य को लगातार कायम रखा है और एक मनस्क होकर एक शांति प्रिय राष्ट्र के मार्ग का अनुसरण किया है। इस प्रकार जापान एशिया और विश्व में शांति और विकास के लिए लगातार योगदान दे रहा है। भारत का भी शांति की स्थापना करने व कई वर्षों से विभिन्न देशों में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संबंध में बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को भेजने का इतिहास रहा है। मेरा विश्वास है कि आज हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जो हम तीव्र विकास देख रहे हैं, उसकी नींव जापान और भारत के प्रयासों से 70 वर्ष पूर्व डाली गयी है जिसमें यह अभिलाषा है कि शांति व समृद्धि की स्थापना हो तथा क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयास हों।

जापान ने जो रास्ता अख्तियार किया है , उसके आधार पर वह अंतरराष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांत पर आधारित ''शांति हेतु अग्रसक्रिय योगदान '' के बैनर के अंतर्गत हिंद-प्रशांत क्षेत्र व विश्व में शांति व स्थिरता में सक्रिय योगदान देना जारी रखेगा। उदाहरण के लिएइसी वर्ष 20 जून को जापान विश्व के साथ एशिया में शांति स्थापना के अपने अनुभवों और सीखों को साझा करने के लिए ''एशिया में शांति स्थापना, राष्ट्रीय एकीकरण और लोकतांत्रीकरण संबंधी उच्च स्तरीय सेमीनार '' की मेजबानी करेगा। इसके अलावा, जापान का भारत के साथ विशेष साझेदारी के आधार पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए नए युग के निर्माण में योगदान देने का इरादा है।

(भविष्य की ओर) देवियों
और सज्जनों,
जापान और भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार साथ काम कर सकता है? मैं इन तीन पुलों को मजबूत करने का प्रस्ताव करना चाहूंगा जो इस क्षेत्र को जोड़ता है।

प्रथम पुल है ''मूल्य और भावना''

सार्वभौमिक मूल्य यथा लोकतंत्र, स्वतंत्रता, खुली अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने व विश्व के केन्द्र के रूप में चमकते रहने के लिए अपरिहार्य है। जापान और भारत एशिया के सबसे सफल लोकतंत्र और स्वतंत्र राष्ट्र हैं। मैं इस पर जोर देना चाहूंगा

कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए दोनों देशों का नेतृत्व आवश्यक है ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों , खुली अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था से समर्थित व्यवस्था स्थापित की जा सके।

इसके अतिरिक्त , सहानुभूति, समावेशी, अहिंसा व मानवता के प्रति स्नेह का विचार एशिया की परंपरागत भावना में निहित है। ऐसी आध्यात्मिक संस्कृतियोंके कारण लोकतंत्र की जड़ें एशिया में मजबूत हैं। भारत, जो बौद्ध धर्म का जन्म स्थल है और जापान जिसने बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों को अपनाया है और अपनी परंपरागत भावना के साथ सामंजस्य बनाया है , को एशियाई आध्यात्मिक के दो प्रमुख मानक धारक के रूप में उल्लेख किया जा सकता है।

जापान और भारत ''मूल्यों'' और ''भावना'' दोनों के संदर्भ में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे वे इस क्षेत्र में एक नेतृत्व वाली स्थिति को अपनाने में समर्थ होंगे और यही एक कारण है कि दोनों देशों के बीच यह साझेदारी इतना खास है।

दूसरा पुल है ''एक जीवंत अर्थव्यवस्था''

जब प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था मूल रूप से एक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों के साथ संबद्ध हो तो एक सहक्रियात्मक प्रभाव सृजित होती है और प्रत्येक अर्थव्यवस्था के महत्व को बढ़ाया जा सकता है। जापान-भारत आर्थिक संबंध जो हाल के वर्षों में मजबूत हुआ है , उसे समग्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अधिक योगदान देने के लिए और संवर्धित किया जाना चाहिए।

अबेनोमिक्स के अंतर्गत जापान की सरकार जापानी उद्यमियों को विदेश में विकास के लिए सहायता प्रदान करती है जबकि भारत मोदीनोमिक्स के अंतर्गत निवेशों को आकर्षित कर अपने निर्माण उद्योग को मजबूत करता रहा है। पिछले वर्ष सितम्बर में हुई शिखर बैठक में हुए ''जापान-भारत निवेश संवर्धन साझेदारी'' समझौते में अबेनोमिक्स और मोदीनोमिक्स के बीच सहक्रिया की कोशिश की गयी। जापान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गयी 'मेक इन इंडिया' पहल में योगदान करेगा ताकि भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में और अंततोगत्वा विश्व के लिए आर्थिक विकास के आधार को मजबूत करने में सहायता मिल सके।

इसके अतिरिक्त ,दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आर्थिक संपर्क को मजबूत करते हुए दक्षिण एशिया और

दक्षिण पूर्व एशिया के बीच समुद्र और भूमि रास्ते से संपर्क को मजबूत करना महत्वपूर्ण है ताकि ये क्षेत्र एक विशाल आर्थिक नेटवर्क तैयार कर सके। इस प्रकार महत्वपूर्ण आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए समग्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए यह संभव होगा। इस दृष्टिकोण से जापान सरकार का इरादा क्षेत्रीय संपर्क में बढ़ोतरी करने के लिए सार्क क्षेत्र में ऊर्जा नेटवर्क के निर्माण हेतु सहायता देने का है। इसके अतिरिक्त, सार्क और आसियान के बीच संपर्क में बढ़ोतरी करेन के लिए जापान पूर्वोत्तर भारत में विकास पहलों को समर्थन देकर अपनी सहायता को मजबूत करेगा जो इन दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करेगा।

इसके साथ-साथ विज्ञान और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश से आर्थिक विकास के फैलाव के लिए आधार प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री अबे और प्रधानमंत्री मोदी पहले ही युवा शोधकर्ताओं के लिए एक्सचेंज कार्यक्रमों के विस्तार के साथ समुद्री प्रौद्योगिकी , समुद्री अवलोकन और बाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हो गये हैं। हम उन चीजों की बुनियाद रखेंगे जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण है उसके बाद उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी के माध्यम से उन्हें विकसित करेंगे।

तीसरा पुल है ''मुक्त और स्थिर समुद्र''

यह क्षेत्र समुद्रों से जुड़ा हुआ है जिसका विस्तार दक्षिण चीन सागर से होते हुए हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक है। भारत और जापान दोनों समुद्री से सटे देश हैं जिनके हित समुद्री लेनों की सुरक्षा पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने ''समुद्री कानून संबंधी तीन सिद्धांत '' का प्रस्ताव दिया है। ये सिद्धांत हैं: अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर दावा करना और उन दावों को स्पष्ट करना, दावा करने की कोशिश करने में ताकत या दवाब का इस्तेमाल नहीं करना; और शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को सुलझाने की कोशिश करना। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन सिद्धांतों के समग्र उपयोग से इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की नींव पड़ेगी।

जापान और भारत रक्षा प्राधिकरणों के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यासों और तट रक्षकों के बीच वार्ता व संयुक्त अभ्यास को लागू कर समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। भारत-अमेरिका मालाबार समुद्री अभ्यासों में यूएस-2 एम्फिबियन एयरक्राफ्ट और जापान की सतत भागीदारी सहित रक्षा उपकरण सहयोग के माध्यम से अपने सहयोग को और मजबूत करना आवश्यक है। इसके अलावा , मेरा विश्वास है कि बहुपक्षीय ढ़ांचे यथा आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) और पूर्वी एशिया शिखर

सम्मेलन (ईएएस) में जापान-भारत सहयोग उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए , हमें अपनी विशेष साझेदारी के तहत "मुक्त और स्थिर समुद्र" की रक्षा करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को अधिक अग्रसक्रिय तरीके से स्वीकार करना चाहिए।

(वैश्विक मुद्दों के संबंध में प्रयास)

देवियों और सज्जनों,

जापान-भारत संबंध का महत्व केवल हिंद-प्रशांत क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यह खास साझेदारी वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए भी उत्तरोत्तर और महत्वपूर्ण होगी।

सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार करने का मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस वर्ष अपना 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। अपने शुरूआत से ही कुछ परिवर्तन के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भर में शांति, विकास और मानवाधिकार के लिए योगदान दिया है। जापान सबसे बड़े हिताधिकारियों में से एक है और इसने संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व पर लगातार जोर दिया है। तथापि , 21वीं सदी की तेजी से बढ़ती चुनौतियों से पर्याप्त रूप से निपटने के लिए हमें वर्तमान अंतरराष्ट्रीय समुदाय की वास्तविकताओं को परिलक्षित करने के लिए सुरक्षा परिषद् के स्थायी और अस्थायी दोनों ही सदस्यों की संख्या को बढ़ाना चाहिए।स्थायी सदस्यों की जिम्मेदारियों को मानने के इरादे और क्षमता के साथ जापान और भारत सुधार का वाहक बनेंगे। 2015 में इस मुद्दे पर ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए जी4 देश यथा जापान, भारत, जर्मनी और ब्राजील अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन प्राप्त करने के लिए साथ कार्य करेंगे।

पेरिस में हुई आतंकी गोलीबारी की घटना ने हमारे विश्वास को और पुष्ट किया है कि आतंकवाद से लड़ाई एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को समग्र प्रयास करना चाहिए। जापान पेरिस में हुई आतंकी घटना सहित इसके सभी रूपों की दृढ़ता से भर्त्सना करता है। आतंकवाद जापान और भारत के लिए एक वास्तविक खतरा है। दो वर्ष पूर्व अल्जीरिया में हुई आतंकी घटना में कई जापानी नागरिकों की जानें चली गयीं थी। साथ ही मैं यह समझता हूं कि भारत के विभिन्न भागों में दु:खद आतंकी घटनाएं होती रही हैं। हमें आतंकवाद का दृढ़ता से मुकाबला करना है।

इसके अतिरिक्त, 2015 परमाणु निशस्त्रीकरण और अप्रसार के लिएएक मील का पत्थर वाला वर्ष है

क्योंकि यह वर्ष परमाणु बम विस्फोट की 70वीं वर्षगांठ था। जापान की सरकार की ओर से विशेषकर हिरोशिमा प्रिफेक्चर से विदेश मंत्री के रूप में मैं इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष अगस्त में परमाणु बम हमले के जापानी पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए भारतीय संसद की सराहना करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि यह जापान के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा देश है जिसने युद्ध के दौरान परमाणु बम का प्रहार झेला है और जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को परमाणु हथियार मुक्त विश्व की ओर ले जाना चाहता है। यद्यपि , हमारी स्थितियों में अंतर बरकरार है किंतु जापान और भारत का यह साझा लक्ष्य है। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम इस बात की संभावना तलाशेंगे कि जापान और भारत अपनी ''विशेष रणनीति और वैश्विक भागीदारी'' के तहत अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार संबंधी प्रयासों को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ कितना सहयोग कर सकता है। जापान ''परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व'' का निर्माण करने के लिए भारत के साथ संयुक्त प्रयासों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेाल में सहयोग के लिए समझौते पर बातचीत को भी आगे बढ़ाना चाहेगा।

प्रश्नोंत्तरी सत्र के दौरान प्रश्न पूछते श्रोतागण

(निष्कर्ष)

देवियों और सज्जनों,

हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति और समृद्धि का 21वीं सदी की दुनिया की शांति व समृद्धि में बड़ा योगदान है। जब प्रधानमंत्री मोदी जापान की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि जापान और भारत के बीच विशेष साझेदारी है जिससे 21वीं सदी में एशिया की दिशा निर्धारित होगी। जापान और भारत जिनके बीच द्विपक्षीय संबंध ऐसा संबंध है जिसमें विश्व के विकास की सबसे अधिक क्षमता है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र को जोड़ने वाले तीनों पुलों को मजबूती प्रदान कर सकता है और इस क्षेत्र की क्षमता को महसूस कर सकता है। हम इस समग्र क्षेत्र और विश्व की शांति व समृद्धि के लिए संयुक्त रूप से नेतृत्व प्रदान करें।

यदि जापान और भारत एक साथ कार्य करें तो मुझे विश्वास है कि हम इस दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***